इलाज के लिए मनमानी राशि देने हेतु बाध्य है। 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' एवं 'आयुष्मान योजना' मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने गरीब को अच्छा इलाज व राहत दी है।

महोदय, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश में संचालित मेडिक्लेम कंपनियां अपने पॉलिसी होल्डर को सस्ती दरों पर इन्हीं निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए समझौता करती हैं, जिनकी दर काफी कम है। इसी प्रकार सीजीएचएस की दर भी है। जब छोटी-छोटी मेडिक्लेम कंपनियां, निजी अस्पतालों से समझौता करके सस्ती दरों पर इलाज करा सकती हैं, तो सरकार क्यों निजी अस्पतालों के लिए दर तय नहीं करती, जिसके आधार पर जनता सस्ती दरों पर इलाज करा सके?

महोदय, सरकार से मेरी मांग है कि निजी अस्पतालों में इलाज हेतु सभी चीजों की दर तय की जाए, जिसके आधार पर आम नागरिक निजी अस्पतालों से सस्ती दरों पर इलाज करा सके।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Naresh Bansal: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat).

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय श्री संजय कुमार झा जी।

Demand for establishment of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) Centre in Bihar

श्री संजय कुमार झा (बिहार) : महोदय, बिहार से उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों जैसे मखाना और लीची का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में केवल मखाना का निर्यात लगभग 300 करोड़ रुपये का था। इसके अलावा, बिहार में भागलपुरी शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान जैसे GI-टैग वाले कृषि उत्पादों की अपार क्षमता है। बिहार के किसान और व्यापारी वर्तमान में वाराणसी में स्थित Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) केंद्र के माध्यम से कृषि निर्यात करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार में पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट निरंतर परिचालन में हैं, और जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह एयरपोर्ट बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात को और आसान बनाएगा।

इस संदर्भ में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिहार में APEDA केंद्र की स्थापना पर विचार करे। इस केंद्र की स्थापना से बिहार के प्रीमियम कृषि उत्पादों जैसे मखाना, लीची और अन्य GI-टैग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह केंद्र मूल्य वर्धित प्रसंस्करण, किसानों को बेहतर प्रशिक्षण और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजारों में बेहतर पहचान मिल सकेगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Sanjay Kumar Jha: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shrimati Phulo Devi Netam. Not present. Shri Dorjee Tshering Lepcha.

Demand for Green Bonus and Special Package for Sikkim State

SHRI DORJEE TSHERING LEPCHA (Sikkim): Sikkim, nestled in the lap of Mount Khangchendzonga, the third highest peak in the world, is a green State with 82 per cent forest land and over 47 per cent forest cover despite over 30 per cent area under snow and rocks which is among the highest in the country. Over 31 per cent Protected Area Network, the highest in the country, boasts a lone National Park, a UNESCO World Heritage site under the mixed category of nature and culture, first of its kind in India.

As the world's mega-biodiversity hotspot, Sikkim harbours 26 per cent of India's biodiversity within just 0.2 per cent of its area. Its 84 glaciers, 534 lakes, and rivers and mountains are crucial for maintaining water cycle and energy security for the nation and beyond.

Sikkim, India's first 100 per cent organic State, won the Future Policy Gold Award, 'Oscar for best policies', from the UN's Food and Agriculture Organisation in 2018; was declared India's cleanest state by NSSO in 2015; won India Today's State of the States Awards for Economy, Environment and Law & Order in 2021; and awarded Best State for Environment Education in 2024 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Despite Sikkim's ecosystem services benefiting the nation and the world, it faces opportunity costs from land-use restrictions for conservation, its commitment to Nationally Determined Contributions & Sustainable Development Goals, and bears financial burdens from natural disasters like recent flash floods and GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), disproportionately shouldering the cost of maintaining its natural treasure.

Therefore, I respectfully request the Government for a Green Bonus and Special Package to help Sikkim manage its financial burden and preserve the nation's vital natural resources.